

क्रोध एक ऐसा तेजाब है, जो उस पात्र को ज्यादा नुकसान पहुँचाता है जिसमें वह रखा जाता है।

TODAY WEATHER



DAY

32°

Hi

NIGHT

28°

Low

संक्षेप

'छात्रों के खिलाफ FIR न करने के वादे पर हम गंभीर', केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

नई दिल्ली, एंजेंसी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पेपर लीक को लेकर विरोध करने वाले छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने के अपने वादे पर वह अब भी गंभीर है। कॉलेरोघ जनता पार्टी (सीजेपी) ने पिछले महीने अपना विरोध प्रदर्शन इस आश्वासन के बाद खत्म कर दिया था कि जवाबदेही और परीक्षा सुधारों की मांग करने के लिए राजधानी के मुख्य इलाके में जमा हुए हजारों वॉलंटियर्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सौलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में कुछ गलतफहमी या गलत जानकारी थी। मुझे यह कहने के निश्चि मिले हैं कि सरकार छात्रों से किए गए उस वादे को लेकर गंभीर है।’ वकील वृंदा ग़ोवर ने यह जानना चाहा कि क्या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएगी या रद की जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह मुद्दा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने से जुड़ा है। उन्होंने कहा, ‘ये युवा हैं जिनकी जिंदगी अभी बाकी है। एफआईआर रद कराने के लिए भी हमारे पास बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एफआईआर हैं। राज्यों के साथ इस मामले को सुलझाने के बाद हम इस कोर्ट में वापस आएंगे।’ इस पर मेहता ने कहा कि इसे चाहे किसी भी कानूनी रूप से मान्य तरीके से किया जाए, सरकार अपने वादे पर कायम है।

नागपुर में गडकरी के घर का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी, पुलिस ने हिरासत में लिया

नागपुर, एंजेंसी। नागपुर पुलिस ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर आवास की ओर मार्च कर रहे भारतीय यु्थ कांग्रेस और एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। मेहुल आडवाणी जैसे स्थानीय नेताओं की अगुवाई में हुए इस विरोध-प्रदर्शन का मुख्य कारण E20 (20% इथेनॉल-मिश्रित) पेट्रोल को अनिवार्य बनाए जाने के खिलाफ जनता का असंतोष था। यु्थ कांग्रेस नेता मेहुल आडवाणी ने कहा, ‘हम हम पर थोपे जा रहे E–20 का विरोध करते हैं। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।’ विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि E20 पेट्रोल से वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंच रहा है और माइलज में गिरावट आ रही है। विशेष रूप से पुराने वाहनों के लिए इसे हानिकारक बताया जा रहा है। यु्थ कांग्रेस ने मांग की है कि उपभोक्ताओं को बिना इथेनॉल वाले सामान्य पेट्रोल को भी खरीदने का स्पष्ट विकल्प मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्र सरकार ने इस नीति का पुरजोर बचाव किया है। सरकार का तर्क है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से भारत के कच्चे तेल के आयात बिल में भारी कटौती होती है, कार्बन उत्सर्जन घटता है और स्थानीय किसानों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचता है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ईंधन से जुड़े अनसुलझे दावों को गैर-वैज्ञानिक और भ्रामक करार दिया है। इस विरोध के बीच नागपुर साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर शिक्का कसा है। भारतीय न्याय संहिता के तहत कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

आर्यावर्त क्रांति व्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के लिए चंदे के प्रबंधन में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग यह मुद्दा उठा रहे हैं, उन्होंने पहले मंदिर निर्माण का विरोध किया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले पत्रकारों से बात करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या का मुद्दा उन लोगों द्वारा उठाया जा रहा है जिन्होंने पहले विरोध प्रदर्शनों के दौरान राम भक्तों के खिलाफ कार्रवाई की थी। योगी ने किसी पार्टी का नाम लिए



बिना कहा कि अयोध्या का मुद्दा वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थीं। ये वही लोग हैं जो ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने पर लाठीचार्ज और गोलीबारी का सहारा

बृजभूषण के बरी होने पर बोलीं विनेश फोगाट– सारा तंत्र बचाने में लगा था, प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरा



नई दिल्ली, एंजेंसी। महिला पहलवानों से उत्पीड़न के मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष रह चुके बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने पर विनेश फोगाट और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विनेश ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। विनेश ने बताया कि सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं। विनेश ने कहा कि पर कई महिला पहलवान खड़ी रहीं और कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहीं। हमें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने बृज भूषण

शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। विनेश ने आरोप लगाया कि शुरु दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है, और यह जल्द से जल्द की जाएगी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई

जारी रखेंगे।

‘ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं’

वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि, “एक तरफ तो वे कहते हैं कि वे युवा पीढ़ी के साथ हैं, महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये हमारे सामने हैं।”

'आयोजकों की जवाबदेही तय हो'

छात्रों के विरोध प्रदर्शन मामले में शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल



नई दिल्ली, एंजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 20 जुलाई के 'संसद चलो' छात्र प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के आयोजकों ने हिंसा के लिए उकसाया। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र सामग्री पोस्ट करने वाले नाबालिगों को आपराधिक कार्रवाई का सामना कराने के बजाय सामुदायिक सेवा कराई जाए। वकील ने कोर्ट में कहा कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के आयोजक सरकार की प्रतिक्रिया के बाद भी भड़काऊ बयान देना जारी रख रहे हैं। वकील ने कोर्ट से कहा, सरकार ने काफी उदार रुख अपनाया है, फिर भी आयोजक आग को भड़का रहे हैं। आयोजक गैर-

प्राथमिकी को लेकर अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। यहां एक समान नीति बनाई जानी चाहिए। इन अधिसूचनाओं से देश के शांतिप्रिय नागरिकों के मन में असंतोष पैदा हो रहा है।

नाबालिगों पर कार्रवाई को लेकर क्या कहा गया?

याचिका में सोशल मीडिया पर अभद्र वीडियो पोस्ट करने वाले नाबालिगों और युवाओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का मुद्दा भी उठाया गया है। वकील ने कहा कि ऐसा व्यवहार सुधार की जरूरत वाला है, लेकिन आपराधिक कार्रवाई इसका सही समाधान नहीं है। वकील ने कहा, दुर्भाग्य से कुछ युवा लड़के और लड़कियां बेहद अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।

दिल्ली के प्रदूषण से दम तोड़ रहा हूमायूं का मकबरा लगातार कैसे हो रहा कमजोर?



नई दिल्ली, एंजेंसी। दिल्ली में UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुमायूं के मकबरे में इस्तेमाल किए गए बलुआ पत्थर खराब होने लगा है। ऐसा दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण हुआ है। ये बात इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की और आईआईटी कानपुर की एक जाईंट स्टडी चली है। स्टडी रिपोर्ट ‘इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आर्किटेक्चरल हेरिटेज’ में प्रकाशित की गई है।

इस स्टडी रिपोर्ट के अनुसार, मकबरे के अलग-अलग भागों से जो काली परतों के सैंपल एकत्र किए गए, उनका विश्लेषण लैब तकनीक के माध्यम से किया गया। इस दौरान रिसर्च करने वाली टीम को पता चला

कि काली परत मुख्य रूप से जिप्सम से बनी है। ये तब बनती है जब प्रदूषित हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड कैल्शियम-युक्त धूल और नमी के साथ प्रतिक्रिया करती है। स्टडी से पता चला है कि जिप्सम की परत में कालिख, धूल और धातु के बारीक कण (जो गाड़ियों से

निकलने वाले धुएं, निर्माण कार्यों, सड़क की धूल, खेती के कचरे को जलाने और औद्योगिक प्रदूषण से आते हैं) फंस जाते हैं, जिससे धीरे-धीरे बलुआ पत्थर पर काली परत बन जाती है। ये भी पाया गया है कि स्मारक के उन हिस्सों में सबसे मोटी काली परत बनी, जो बारिश से बचे

थीं। उन्होंने कहा कि वे राम मंदिर के लिए मिले दान की चोरी की बात तो करते हैं, लेकिन मंदिर के निर्माण के लिए उनकी जेब से एक पैसा भी नहीं आया। देश और दुनिया उनके दोहरे मापदंड देख रही है।

उनके ये बयान तब आए जब समाजवादी पार्टी (SP) के विधायकों ने सत्र के पहले दिन विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर चंदे से जुड़े कथित मामले, NEET पेपर लीक, बिजली की समस्या और खाद की कमी को लेकर नारे लगाए। SP नेता शिवपाल सिंह यादव ने तीन दिन का सत्र बुलाने के लिए सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि वह जनता से जुड़े

अहम मुद्दों पर चर्चा से बच रही है।

यादव ने पत्रकारों से कहा कि तीन दिन का सत्र बुलाकर यह सरकार निंदनीय काम कर रही है। राज्य में कई समस्याएं हैं और सरकार इन मुद्दों से भाग रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान SP विधायकों ने चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए और BJP सरकार पर जनता की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि SP बिना किसी ठोस एजेंडे के मुद्दे खड़े करने की कोशिश कर रही है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी विपक्ष पर मुद्दों और एजेंडे की कमी का आरोप लगाया।

नायडू सरकार में कानून व्यवस्था चौपट, बदले की राजनीति चरम पर: जगन

नई दिल्ली, एंजेंसी। युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू पर लोख़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था खत्म हो गई है और जंगल राज चल रहा है, जिसमें विपक्ष के खिलाफ मुद्दे की राजनीति की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जारी एक लंबे बयान में, YSRCP प्रमुख ने हाल ही में आधी रात को हुई पुलिस की छापेमारी और पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। रेड्डी ने ख़ास तौर पर अलुर के विधायक विरुपाक्षी के मामले का जिक्र किया। जगन ने कहा कि नारा चंद्रबाबू नायडू के शासन में कानून-व्यवस्था का बुरा हाल है। हमलावरों को सुरक्षा मिलती है और पीड़ितों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं: यह बदले की राजनीति है।

अमेरिका में पढ़ाई का पैसा कहां से आया? : आरटीआई एक्टिविस्ट के सवाल का दीपके ने दिया जवाब, सरकार को भी दी चेतावनी



जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। लेकिन उनकी जगह प्रह्लाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाए जाने का CJP समर्थन नहीं करती। दीपके ने आरोप लगाया कि प्रह्लाद जोशी विलकिस बानो मामले के दोषियों का सम्मान करते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी देना उचित नहीं है। स्कूल जाने वाली लड़कियां इस तरह के

घटनाक्रम से क्या संदेश लेंगी।छत्रपति संभाजीनगर में पार्टी के भविष्य पर बोल्ते हुए दीपके ने साफ किया कि उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में ईंडी और सीबीआई के जरिए राजनीतिक दलों को तोड़ा जा रहा है। चुनावों में वोट डिलीट किए जा रहे हैं। जनता का न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली और मीडिया से भरोसा उठ रहा है।

बृजभूषण शरण सिंह के बाइज्जत बरी होने से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कई सारे समीकरण बदलने वाले हैं

करीब तीन वर्षों तक देश की राजनीति, खेल जगत और मीडिया के केंद्र में रहे पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को आखिरकार दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से बड़ी राहत मिल गई। महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। वैसे बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के समर्थन में जिस तरह तमाम विपक्षी नेता खड़े हो गये थे उसके चलते यह सब कुछ शुरू से ही राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रहा था। उल्लेखनीय है कि जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन कराया गया था और धरने के मंच पर तमाम बड़े विपक्षी नेता पहुंचे थे और मंच से दिये गये भाषणों के जरिये भाजपा को महिला विरोधी बताया जा रहा था। साथ ही बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देशभर में माहौल बनवाने और मीडिया ट्रायल के जरिये उनकी छवि बिगाड़ने के तमाम प्रयास किये गये थे।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आज भी संसद में विपक्ष का प्रदर्शन, जया बच्चन–डिंपल यादव ने किया दान



नई दिल्ली, एंजेंसी। राम मंदिर में दान चोरी मामले में आज भी संसद परिसर में विपक्षी पार्टियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। सपा सांसद जया बच्च ने सांकेतिक दान पेटी में रुपये डाले और दान किया। उस पर दान चोरी का पोस्टर लगा हुआ था। इस मामले में सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, “ये मुद्दे को भटकाने के लिए है। सरकार से लोग दुखी हैं। जिस प्रकार से चंदा चोरी की गई, जमीनों में घोटाले किए गए इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आज तक एक पर भी FIR क्यों दर्ज नहीं हुई?” उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुद्दे को भटकाने के लिए है। ये जो सरकार है, सरकार में पूरी तरह से निराशा की, भावना है और लोग सरकार से निराश हैं। डिंपल ने कहा कि बड़े-बड़े लोग आखिरकार जो चंदा और जो दान-पेटी की जो पैसा थर, लोगों ने धातुएं जो दी थीं प्रभु श्री राम के चरणों में जो अर्पित

की थीं। ये निश्चिततौर पर श्रद्धा के भाव से, निष्ठा के भाव से... वह आखिरकार गई कहां? सपा सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर ‘सनातन धर्म के अपमान’ के मामले में दर्ज हुई FIR सिर्फ विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश

है। पत्रकारों से बातचीत में डिंपल यादव ने दावा किया कि सरकार जनता के बढ़ते असंतोष का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि इस FIR का मकसद 'राम जन्मभूमि भूमि घोटाले' और 'राम मंदिर दान चोरी विवाद' से ध्यान हटाना है। उन्होंने कहा, “ये सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है। जनता के बीच (सरकार को लेकर) पूरी तरह से निराशा और मोहभंग का माहौल है।”

नीट पीड़ितों के मुआवजे पर उठाए सवाल

दीपके ने नीट अभ्यर्थियों की मौतों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। सीजेपी की दूसरी मांग आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की थी। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से सहायता नहीं मिली है। दीपके ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ नियमों और प्रक्रियाओं का बहाना बना रही है।जब विधायकों और सांसदों की खरीदने की बात आती है तो करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। लेकिन पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के समय नियमों का हवाला दिया जाता है।

पीएम मोदी पर ट्रंप का दबाव ! ई20 पर केजरीवाल का मार्च का ऐलान



नई दिल्ली, एंजेंसी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि वे मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास तक एक मार्च का नेतृत्व करेंगे। इस मार्च का मकसद ई20 पेट्रोल के रोलआउट का विरोध करने वाली एक ऑनलाइन याचिका सौंपना है, जिस पर 2,00,000 से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि E20 पेट्रोल से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा के लिए ऑर्गेंटमेंट मांगने के लिए पिछले महीने प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र का कोई जवाब न मिलने पर वे खुद ये याचिकाएं सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि इन याचिकाओं में इस ईंधन से जुड़ी गाड़ियों की समस्याओं के बारे में लोगों की शिकायतें शामिल हैं।

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भारत ने अमेरिका से इथेनॉल खरीदने के लिए ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को लगातार बढ़ावा देना किसी छिपे हुए एजेंडे की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि मैं कल 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाऊंगा ताकि जनता के

हस्ताक्षर वाली अर्जियां उन्हें व्यक्तिगत रूप से सौंप सकूँ और इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकूँ। लोगों को अपनी गाड़ियों को लेकर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी सरकार इसे जारी रखे हुए है; इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई छिपा हुआ एजेंडा है।

खेल में अपनी प्रतिभा को पहचाने और भविष्य संवारेें

एक समय था जब यह माना जाता था कि केवल पढ़ाई-लिखाई ही उज्ज्वल भविष्य और अच्छी नौकरी का मार्ग है। इसी सोच को दर्शाते हुए कहा जाता था- "पढ़ोगे-लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे बनोगे खराब।' लेकिन आज का भारत इस धारणा को पूरी तरह बदल चुका है। इसलिए आज के दौर में यह कहना उचित नहीं होगा कि केवल पढ़ाई-लिखाई ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। यदि किसी में खेल के प्रति जुनून, अनुशासन और समर्पण है, तो वह खेलों के माध्यम से भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। शिक्षा और खेल, दोनों मिलकर व्यक्तित्व का समग्र विकास करते हैं तथा जीवन में सफलता के नए द्वार खोलते हैं।

खेल केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण, आत्मविश्वास, अनुशासन और सफलता की ऐसी पाठशाला है, जहाँ से भविष्य के विजेता तैयार होते हैं। आज खेलों में करियर की असीम संभावनाएँ हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान, रोजगार, आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक पहचान मिल रही है। ऐसे समय में प्रत्येक युवा के लिए आवश्यक है कि वह अपनी खेल प्रतिभा को पहचाने और उसे सही दिशा देकर अपने भविष्य को संवारे। हर बच्चे के भीतर कोई न कोई विशेष क्षमता होती है। किसी की गति उसे उत्कृष्ट धावक बनाती है तो किसी की फुर्ती कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल या अन्य खेलों में सफलता दिला सकती है। यदि प्रतिभा को समय पर प्रशिक्षण और अवसर मिले, तो वही खिलाड़ी प्रदेश और देश का गौरव बनता है। खेलों का सबसे बड़ा योगदान यह है कि वे जीवन के महत्वपूर्ण गुणों का विकास करते हैं। अनुशासन, धैर्य, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, समय प्रबंधन और संघर्ष का साहस खेल के मैदान में ही सीखा जाता है। यही गुण आगे चलकर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नींव रखते हैं। छत्तीसगढ़ में खेलों को नया स्वरूप देने की दिशा में राज्य शासन ने उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने, ग्रामीण और जनजातीय अंचलों के युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने तथा खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए अनेक पहल की जा रही हैं। प्रदेश में आधुनिक खेल अर्थोसंरचना का विकास, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार, खेल अकादमियों को सुदृढ़ करना तथा विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसी के साथ ही इस वर्ष से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खेलों इंडिया टुडैबल गेम्स का सफल आयोजन किया गया है। विशेष रूप से बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक जैसी अभिनव पहल ने खेलों को गाँव-गाँव तक पहुँचाया है। इन आयोजनों ने दूरस्थ वर्नांचलों और जनजातीय क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया है। परंपरागत खेलों के साथ आधुनिक खेलों को भी बढ़ावा देकर हजारों युवाओं, महिलाओं और बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। इन प्रतियोगिताओं ने यह साबित किया है कि अवसर मिलने पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के खिलाड़ी अब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं।

इसके साथ ही विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं, ग्रामीण खेल आयोजनों, प्रतिभा खोज कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से नई प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, सम्मान और विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर कई पुरस्कार प्रदान करती है। जिसमे गुंडाधुर सम्मान शामिल है। यह छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार बस्तर के वीर नायक गुंडाधुर की स्मृति में, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। दूसरा महाराज प्रवीरचंद भंजदेव के नाम पर है। यह पुरस्कार विशेष रूप से तीरंदाजी के खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में खेल प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है, जिससे युवाओं में खेल का अवसर प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। वर्तमान में ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (ग्लासगो) में महिला 53 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। अमितेश कुजूर ने राष्ट्रमंडल खेल में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसी प्रकार अन्य खिलाड़ियों ने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है।

व्यंग्य

सचमुच नई पीढ़ी का आंदोलन



नीट यूजी पेपर लोक के खिलाफ जंतर मंतर का आंदोलन सचमुच नई पीढ़ी का आंदोलन थे। सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि नई पीढ़ी के लोग इसमें शामिल हुए। वह एक पहलु है कि वयस्क होने से पहले की उम्र वाले किशोर और युवा इस आंदोलन का हिस्सा बने। इस लिहाज से भी यह नई पीढ़ी का आंदोलन था कि इसमें नए साधनों और नए माध्यमों का खुल कर इस्तेमाल हुआ। छात्र और युवा सोशल मीडिया के जरिए अपना नैरेटिव बना रहे हैं। उनकी रचनात्मकता देkhना वाली है। वे पारंपरिक मीडिया या पुराने व स्थापित सोशल मीडिया हैड्ल्स के भरोसे नहीं हैं। वे अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं और उसे प्रचारित कर रहे हैं।

तभी उनके ऊपर इस बात का असर नहीं पड़ा कि मीडिया या सोशल मीडिया इसको कैसे दिखाता है और सरकार किस तरह से इसकी साख़ विगाड़ने का प्रयास करती है। वह प्रयास होता रहा लेकिन उस पर भारी युवाओं का अपना कंटेंट था। उन्होंने बहुत प्रभावी तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया।

इसी तरह ऐप बेस्ड सेवाओं का इस्तेमाल जैसा इस आंदोलन में हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। वैसे भी नए समय का पहला बड़ा आंदोलन है। तभी कई दिन तक नई दिल्ली के आसपास के सारे मेट्रो स्टेशन बंद रहने पर भी छात्रों को परेशानी नहीं हुई। उन्होंने सबके रास्ते निकाले। ऐप बेस्ड कैब सेवाएं हों या ऐप बेस्ड फूड डिलीवरी की सेवा हो, जंतर मंतर पर सबका इस्तेमाल हुआ।

इसी तरह आंदोलनकारी अपने नारों और कंटेंट में भी बहुत अलग हैं। वे पुराने नारों से अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। बहुत लोगों को बुरा लगा है और वे पुराने जमाने के नारे लिख कर बता रहे हैं कि पहले कितना सारगर्भित और साफ सुथरा नारा हुआ करता था। यह भी कहा जा रहा है कि युवाओं के नारे अश्लील हैं और इससे उनका आंदोलन प्रभावित हो रहा है। लेकिन इस तरह की बातों से युवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है। वे विना किसी शर्मिंदगी या विना किसी माफ़ीनामे के अपनी बात कह रहे हैं। पहली बार सरकार और भाजपा के पूरे इकोसिस्टम को लगा कि छात्रों व युवाओं के जिस समूह के साथ प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते थे या जिनके लिए एजाम वारियर्स नाम से किताब लिखी है वे नाराज होते हैं तो क्या कर सकते हैं? अब तक सरकार ने उनका सद्भाव देखा था लेकिन अब उन्होंने नाराजगी दिखाई है। सद्भाव और समर्थन दिखाने का उनका तरीका भी वैसा था, जैसे विशेष दिखाने का है। पहले वे इस तरह की बातों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के लिए करते थे, तब सरकार और भाजपा के इकोसिस्टम को यह सब अच्छा लगता था। लेकिन अब उन्हीं की दवाई से उनका इलाज हो रहा है तो बुरा लग रहा है।

मध्य पूर्व में उथल-पुथल से भारत-खाड़ी संबंधों के लिए चुनौतियां

जीसीसी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलती है। साथ ही, खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी भारत के साथ व्यापार पर काफी हद तक निर्भर हैं।

इससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलती है। साथ ही, खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी भारत के साथ व्यापार पर काफी हद तक निर्भर हैं।

ब्लॉग

Nepa1 में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा की चिंगारी क्या समूचे हिंदू समाज के लिए खतरे की घंटी है?

नीरज कुमार दुबे

नेपाल के जिस कप्तानगंज इलाके से इस हिंसा की शुरुआत हुई, वह भारत के बिहार से लगी खुली सीमा के बेहद करीब स्थित है। यह क्षेत्र सुनसरी जिले की देवानगंज ग्रामीण पालिका के अंतर्गत आता है, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय दशकों से एक-दूसरे के पड़ोसी के रूप में रहते आए हैं।

नेपाल की तराई इस समय किसी शांत पहाड़ी देश की तस्वीर नहीं, बल्कि ऐसी बारूद की ढेरी नजर आ रही है, जहां एक मामूली चिंगारी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। कांवड़ यात्रा की तैयारियों के दौरान डीजे की तेज आवाज को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़पों में बदल गया। पथर चले, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी, चेतारवनी के तौर पर फायरिंग हुई और आधिकारक गोलियां चलीं। तीन लोगों की मौत ने इस विवाद को स्थानीय घटना से उठाकर राष्ट्रीय संकट का रूप दे दिया।

हिंसा की शुरुआत सुनसरी जिले के देवानगंज क्षेत्र से हुई, लेकिन जल्द ही इसकी आग धनुषा, सिराहा, सप्तरी और जनकपुर सहित नेपाल के दक्षिणी तराई क्षेत्र में फैल गई। प्रशासन को कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा, जबकि पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, प्रदर्शन और सभाओं पर रोक लगा दी गई। नेपाल सेना तक को तैनात करना पड़ा, जिससे हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

नेपाल के जिस कप्तानगंज इलाके से इस हिंसा की शुरुआत हुई, वह भारत के बिहार से लगी खुली सीमा के बेहद करीब स्थित है। यह क्षेत्र सुनसरी जिले की देवानगंज ग्रामीण पालिका के अंतर्गत आता है, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय दशकों से एक-दूसरे के पड़ोसी के रूप में रहते आए हैं। स्थानीय बाजार, स्कूल और सामाजिक जीवन दोनों समुदायों के बीच साझा रहे हैं। यही नजदीकी सामान्य दिनों में सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बनती है, लेकिन तनाव की स्थिति में यही भौगोलिक निकटता छोटी-सी कहासुनी को भी कुछ ही घंटों में बड़े सांप्रदायिक टकराव में बदल देने का खतरा पैदा कर देती है।

हम आपको यह भी बता दें कि स्थिति कुछ सामान्य होने पर प्रशासन ने चुनिंदा इलाकों में कर्फ्यू में ढील देना शुरू किया है। हालांकि कई संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। अस्पताल, एंबुलेंस, दवा, दूध, ईंधन और आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। इसी के साथ विभिन्न जिलों में शांति रैलियां निकाली जा रही हैं,

प्रोफ़ेसर (डॉ.) डी. के. पांडेय

गल्फ कोऑपरेशन कार्डसिल (जीसीसी) एक समूह के तौर पर, विकासशील भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीसीसी के सदस्य देशों के भारत के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और सभ्यतागत संबंध बहुत पुराने हैं। हाल के वर्षों में, यह संबंध पारंपरिक खरीदार-विक्रेता रिश्ते से आगे बढ़कर एक रणनीतिक गठबंधन में बदल गया है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, रक्षा सहयोग और वहां रहने वाले भारतीयों का कल्याण शामिल है। इस क्षेत्र में मौजूद तेल और गैस के बड़े भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद अहम हैं।

जीसीसी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलती है। साथ ही, खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं भी भारत के साथ व्यापार पर काफी हद तक निर्भर हैं। यह जीसीसी और भारत की संयुक्त कोशिश है, जिससे इस क्षेत्र की तरक्की और खुशहाली में मदद मिलेगी। कई संयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने की क्षमता है। आपसी संबंधों को गहरा करने के लिए व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे और लोगों के बीच आपसी संपर्क में सहयोग बढ़ाना कारगर साबित हुआ है।

प्रवासी और रেমिटेंस (विदेश से भेजा गया पैसा): दक्षिण एशियाई व्यापार और व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रवासी कामगारों से काफी समर्थन मिलता है। जीसीसी देशों में लगभग 1 करोड़ (10 मिलियन) भारतीय रहते हैं। जीसीसी देशों ने इस क्षेत्र के विकास में भारतीय समुदाय की भूमिका को माना है। यह पश्चिमी एशिया (मुख्य रूप से जीसीसी) और दक्षिण एशिया के बीच व्यापार और रেমिटेंस की स्थिति है, जो हाल के आंकड़ों पर आधारित है। वित्त वर्ष 2024-25 में, भारत को दुनिया भर से रिकॉर्ड 135.46 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला। विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिला है। 2024 में मेक्सिको दूसरे स्थान पर रहा, जहां 68 अरब डॉलर आने का अनुमान है। तीसरे स्थान पर चीन रहा, जहां अनुमानित 48 अरब डॉलर आए।

भारत को मिलने वाले कुल रेमिटेंस में जीसीसी देशों की हिस्सेदारी लगभग 38% है, जो इस क्षेत्र में बड़ी आर्थिक आमद का जरिया है। भारत में

रेमिटेंस पर निर्भरता कुछ खास इलाकों तक सीमित है; अकेले यूएई से भारत को कुल रेमिटेंस का लगभग 19.2% हिस्सा मिलता है। इसके बाद सऊदी अरब का स्थान है, जहां से 6.7% रेमिटेंस आता है। भारत में आने वाले कुल रेमिटेंस (हर साल लगभग \$27–28 बिलियन) में महाराष्ट्र का हिस्सा करीब 20.5% है, और केरल का हिस्सा करीब 19.7% (लगभग \$26–27 बिलियन) है। इसलिए, खाड़ी देशों (गल्फ) में मंदी का इन दोनों राज्यों पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जीसीसी की कुल आबादी 6.15 करोड़ (61.5 मिलियन) है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) \$2.3 ट्रिलियन है। कुल द्विपक्षीय व्यापार (वित्त वर्ष 2024-25) \$178.56 बिलियन का है। सितंबर 2025 तक भारत में जीसीसी का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) \$31.14 बिलियन से ज्यादा हो गया है। भारत इंजीनियरिंग का सामान, चावल, कपड़ा, मशीनरी, रत्न और आभूषण एक्सपोर्ट करता है; और कच्चा तेल, द्रवरूप प्राकृतिक गैस (एलएनजी) , पेट्रोकेमिकल्स और सोना जैसी कीमती धातुएं इंपोर्ट करता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत-खाड़ी व्यापार रिकॉर्ड \$178.56 बिलियन तक पहुँच गया, जो भारत के कुल ग्लोबल व्यापार का 15.42% है। इसमें \$56.87 बिलियन का एक्सपोर्ट और \$121.68 बिलियन का इंपोर्ट शामिल है — जिससे जीसीसी भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ब्लॉक बन गया है, जो भारत के ग्लोबल व्यापार का 15.42% है। पाँच साल का ट्रेंड: द्विपक्षीय व्यापार सालाना औसतन 15.3% की दर से बढ़ा है। भारत और जीसीसी ने फरवरी 2026 में औपचारिक रूप से मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) बातचीत शुरू की। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, 2030 तक इस कॉरिडोर में कुल व्यापार \$250 बिलियन से ज्यादा हो सकता है।

यूएई के साथ व्यापार \$100 बिलियन से ज्यादा (सीईपीए) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग \$101.25 बिलियन) रहा, जिसमें भारत का व्यापार घाटा \$26.53 बिलियन था; भारत ने \$37.36 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और \$63.89 बिलियन का इंपोर्ट किया। सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन के साथ व्यापार क्रमशः \$41.87 बिलियन (भारत का दूसरा सबसे बड़ा जीसीसी पार्टनर), \$14.14 बिलियन,

\$10.61 बिलियन, \$1.64 बिलियन का रहा। भू-राजनीतिक चुनौतियों से निपटना अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति में तेजी से हो रहे बदलावों के कारण भारत-जीसीसी सहयोग के सामने चुनौतियां हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच, सबसे बड़ी चुनौती जीसीसी देशों और भारत के लिए आर्थिक निर्भरता रही है, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा) की ओर वैश्विक शुकाव के कारण यह संबंध खतरे में है। भारत एक मुश्किल कूटनीतिक स्थिति में है, जहाँ उसे ईरान, इजराइल और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय दुश्मनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना पड़ रहा है, खासकर तब जब खाड़ी देश पारंपरिक पश्चिमी सहयोगियों से आगे बढ़कर उभरते एशियाई देशों के साथ नए रणनीतिक गठबंधन बना रहे हैं। इस क्षेत्र का सुरक्षा ढांचा भी बदल रहा है।

इन भू-राजनीतिक बाधाओं के बावजूद, भारत-जीसीसी सहयोग को नया रूप देने और उसे बेहतर बनाने के लिए कई रणनीतिक कदम उठाए जा सकते हैं। आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने और व्यापारिक जोखिमों को कम करने की दिशा में पहला कदम भारत-जीसीसी एफटीए को जल्द से जल्द पूरा करना है। दूसरा कदम यह है कि सहयोग केवल ऊर्जा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए...इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल हाइड्रोजन, खाद्य सुरक्षा, अहम टेक्नोलॉजी और मिलिट्री मैनुफैक्चरिंग जैसे भविष्य से जुड़े क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। कई बुनियादी रणनीतियां द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकती हैं और उन्हें भू-राजनीतिक तनावों से बचा सकती हैं: द्विपक्षीय जुड़ाव के ढांचे को क्षेत्रीय से वैश्विक स्तर पर ले जाना: मध्य पूर्व की क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं की नाजुकता और बहु-ध्रुवीय प्रकृति के कारण, भारत एक व्यापक क्षेत्रीय नीति से हटकर अधिक लक्षित द्विपक्षीय जुड़ाव के दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है। जीसीसी सदस्यों के साथ अलग-अलग बातचीत करके भारत भू-राजनीतिक तनाव वाले मुद्दों से बच सकता है। इससे उसे खाड़ी देशों के आपसी मुद्दों, जैसे राजनयिक संकट और ऐतिहासिक नाकेबंदी, को सुलझाने में मदद मिलेगी। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी



ताकि दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाल किया जा सके। जनकपुर में सर्वदलीय बैठक आयोजित कर राजनीतिक दलों, धार्मिक नेताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने का प्रयास भी किया गया।

उधर, इस मुद्दे पर लगातार आलोचना झेलने के बाद प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह ने पहली बार राष्ट्र की संबोधित किया। उन्होंने हिंसा की निषण्ण जांच के लिए समिति गठित करने की घोषणा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने नागरिकों से अफवाहों और नफरत फैलाने वाले संदेशों से बचने तथा केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की। सरकार ने मृतकों के परिजनों को दस-दस लाख नेपाली रुपये का मुआवजा देने और उन्हें शहीद घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने का भी वादा किया है।

लेकिन सवाल केवल इतना नहीं है कि हिंसा कैसे भड़की। असली चिंता यह है कि नेपाल, जिसे लंबे समय तक धार्मिक सह-अस्तित्व का उदाहरण माना जाता था, वहां अब सामाजिक ध्रुवीकरण की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देने लगी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि स्थानीय विवाद, सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें, कमजोर प्रशासनिक प्रतिक्रिया, बेरोजगारी और समुदायों के बीच बढ़ता अविश्वास ऐसे हालात को और विस्फोटक बना रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि इस घटना को केवल हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक, सामाजिक और संस्थागत कारण भी मौजूद हैं।

दरअसल, नेपाल की तराई पहली बार बड़े

पैमाने पर हिंसा का गवाह नहीं बनी है। वर्ष 2007 का गौर नरसंहार, कपिलवस्तु की जातीय हिंसा और 2015 की टीकापुर घटना इस क्षेत्र की संवेदनशील सामाजिक संरचना की याद दिलाती हैं। इन घटनाओं का स्वरूप धार्मिक नहीं था, बल्कि जातीय और राजनीतिक संघर्षों से जुड़ा था। लेकिन इन सभी घटनाओं में एक समानता स्पष्ट दिखती है कि बड़ी भीड़ रही, प्रशासन की देर से प्रतिक्रिया आई और स्थानीय तनाव ने तेजी से हिंसक रूप ले लिया। यही कारण है कि आज धार्मिक विवाद भी उसी संवेदनशील सामाजिक ढांचे में और अधिक विस्फोटक साबित हो रहे हैं।

इसी संदर्भ में नेपाल में बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ राजनीतिक समूह नेपाल की बदलती जनसंख्यिकीय और धार्मिक राजनीति को लेकर चिंता जता रहे हैं तथा इसे बढ़ते इस्लामी प्रभाव या पहचान-आधारित राजनीति से जोड़ रहे हैं, जबकि अन्य विशेषज्ञ इसे सामाजिक अविश्वास, आर्थिक निराशा तथा राजनीतिक ध्रुवीकरण का संयुक्त परिणाम मानते हैं। देखा जाये तो नेपाल इस समय धार्मिक पहचान की राजनीति के बढ़ते प्रभाव का सामना कर रहा है, जिससे सभी समुदायों के बीच तनाव बढ़ने का जोखिम पैदा हुआ है।

हम आपको बता दें कि नेपाल की 2021 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 5 प्रतिशत है, लेकिन मधेश और तराई के कई सीमावर्ती जिलों में उनकी हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। सुनसरी, धनुषा, रौतहट, पर्सा और सराही जैसे जिले भारत की खुली सीमा से जुड़े हैं, जहां वर्षों पुराने पारिवारिक, वैवाहिक और व्यापारिक रिश्ते बिहार

तथा उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि सीमा के दोनों ओर पैदा होने वाले सामाजिक या सांप्रदायिक तनाव एक-दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। भारत के लिए चुनौती केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि अफवाहों, कट्टरपंथी प्रचार, संगठित उकसावे और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाले दुष्प्रचार पर भी सामान रूप से नजर रखना आवश्यक होगा।

भारत के लिए यह घटनाक्रम विशेष महत्व रखता है क्योंकि हिंसा प्रभावित अधिकांश जिले भारतीय सीमा से लगे हुए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश से सटी खुली भारत-नेपाल सीमा दोनों देशों की सबसे बड़ी ताकत भी है और संवेदनशीलता भी। यदि नेपाल में सांप्रदायिक तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो उसका असर सीमा पार सामाजिक संबंधों, व्यापार, सुरक्षा और खुफिया चुनौतियों पर भी पड़ सकता है। भारत को नेपाल के साथ सुरक्षा समन्वय, सीमा पर सतर्क निगरानी, अफवाहों और कट्टरपंथी प्रचार पर नजर तथा स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर सूचना साझाकरण को और मजबूत करना होगा।

नेपाल फिलहाल हिंसा की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तविक चुनौती केवल कर्फ्यू हटाने की नहीं, बल्कि टूटते सामाजिक विश्वास को फिर से जोड़ने की है। यदि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन और समाज मिलकर समय रहते इस संकट का स्थायी समाधान नहीं खोजते, तो यह घटना भविष्य में और बड़े सामाजिक टकरावों की चेतावनी साबित हो सकती है। नेपाल की शांति केवल नेपाल का विषय नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत की सुरक्षा और स्थिरता से भी गहराई से जुड़ी हुई है।



कई लोगों को अक्सर कब्ज की परेशानी रहती है। ऐसे में इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज करने के बजाय खानपान पर ध्यान देना जरूरी है। आइए जानते हैं कब्ज से राहत पाने के लिए डाइट में किन हेल्दी फूड्स को शामिल करना चाहिए।

A vibrant assortment of fresh vegetables arranged on a rustic wooden surface. The collection includes a large head of broccoli, several bright orange carrots, a halved beet showing its deep red interior, a green bell pepper, a whole orange pumpkin, a head of cauliflower, a corn on the cob, and various leafy greens like basil and spinach. There are also cherry tomatoes, cucumbers, okra, and small bowls containing green peas and grains. The vegetables are presented in a natural, appealing way, emphasizing their freshness and variety.

गिंगम प्रिंट वाली स्कर्ट फिर चलन में आई, जानिए स्टाइल करने के 5 सुझाव



सर्दियों में गिंगम प्रिंट वाली स्कर्ट के साथ बूट्स पहनना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, जिससे लंबाई भी बढ़ सकती है। ऊंची हील वाले बूट्स आपसे तुलना को और भी खास बनाएंगे और आपको ठंड से भी बचाएंगे। इसके अलावा आप इस मेल को किसी पार्टी या खास मौके पर भी पहन सकती हैं।

बूट्स और गिंगम प्रिंट की स्कर्ट का यह मेल आपको स्टायलिश और आरामदायक दोनों महसूस कराएगा।

महंगाई की मार : टूथपेस्ट से लेकर पेंट तक महंगे होंगे रोजमर्रा के सामान ! त्योहारों से पहले बढ़ेंगी कीमतें

त्योहारी सीजन से पहले आम लोगों की जेब पर महंगाई का एक और असर देखने को मिल सकता है। देश की कई बड़ी कंज्यूमर कंपनियों रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। कच्चे माल और ऊर्जा लागत में तेजी के चलते टूथपेस्ट, डिटजेंट, पेंट, टायर और अन्य सामान महंगे हो सकते हैं। इससे आने वाले महीनों में घरेलू खर्च और बढ़ने की आशंका है।

महंगे होंगे रोजमर्रा के कई सामान

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनियां एक बार फिर कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान यूनिलीवर, डोडला डेयरी और एशियन पेंट्स समेत कम से कम सात कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजों के बाद निवेशकों से बातचीत और मीडिया ब्रीफिंग में कीमतें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के मुख्य वित्त अधिकारी निरंजन गुप्ता ने कहा कि कच्चे तेल से जुड़े उत्पादों की लागत में लगातार तेजी बनी हुई है। इसी वजह से डिटजेंट और डिशवॉशिंग बार जैसे होम केयर उत्पादों में चरणबद्ध तरीके से कीमतें बढ़ाई जाएंगी।



ऊर्जा लागत और महंगाई बना रही दबाव

रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के कारण ऊर्जा और कच्चे माल की कीमतों में तेजी आई है। इसका असर कंपनियों की उत्पादन और लॉजिस्टिक लागत पर भी पड़ा है। इसी दबाव के चलते हैवेल्स इंडिया अपने उत्पादों की कीमतें 8 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है। वहीं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नमक की कीमत भी करीब 7 प्रतिशत बढ़ चुकी है। वित्त मंत्रालय ने भी कहा है कि अब महंगाई का दबाव सिर्फ खाद्य वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ईंधन और मौसम की वजह से दूसरे उपभोक्ता उत्पाद भी प्रभावित हो रहे हैं।

त्योहारी सीजन और आरबीआई की नजर

अगस्त से नवंबर तक का समय भारत में त्योहारी सीजन माना जाता है और इसी दौरान कई कंपनियों की सालाना बिक्री का करीब एक तिहाई हिस्सा आता है। ऐसे में कंपनियों को उम्मीद है कि मजबूत मांग के कारण वे बड़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक का महंगाई लक्ष्य 4

प्रतिशत है, लेकिन जून में खुदरा महंगाई करीब डेढ़ साल बाद इस स्तर से ऊपर पहुंच गई। आरबीआई का अनुमान है कि मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में औसत महंगाई 5.11 प्रतिशत रह सकती है। केंद्रीय बैंक ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और 3 से 5 अगस्त के बीच होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसले पर सभी की नजर रहेगी।

मांग बनी हुई है मजबूत, लेकिन कंपनियों की नजर बाजार पर

रिपोर्ट के अनुसार, अब तक ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की मांग स्थिर बनी हुई है। रितिलस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक जून में खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 6 प्रतिशत बढ़ी, जो मई के मुकाबले बेहतर रही। हालांकि कंपनियां अब यह भी देख रही हैं कि कीमतें बढ़ने के बाद ग्राहकों की खरीदारी पर कितना असर पड़ता है। साथ ही मानसून और पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति आने वाले समय में महंगाई की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाना हुआ आसान! कंफर्म टिकट पर ऑनलाइन लगेज बुकिंग की सुविधा शुरू



31 जुलाई से कंफर्म ट्रेन टिकट वाले पैसेंजर्स के लिए इंडियन रेलवे की ऑनलाइन सामान बुकिंग सुविधा उपलब्ध होगी। इस नई सुविधा का असल मकसद लगेज बुकिंग को ज्यादा सुविधाजनक और आसान बनाना है। आइए आपको बताते हैं आखिर इसको लेकर किस तरह की अपडेट इंडियन रेलवे सामने लेकर आया है।

रेलवे लगेज ले जाने के नियमों को आसान और सुविधाजनक बना रहा है।

कोई भी कर्मशियल सामान को पर्सनल लगेज के तौर पर बुकिंग नहीं कर सकेगा। इंडियन रेलवे 31 जुलाई से कंफर्म ट्रेन टिकट वाले पैसेंजर्स के लिए पर्सनल लगेज (निजी सामान) की ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने जा रहा है। इस नई सुविधा का मकसद लगेज बुकिंग को ज्यादा सुविधाजनक बनाना और पार्सल बुकिंग के प्रोसेस को आसान बनाना है। 20 जुलाई, 2026 के एक पत्र में, रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिया कि वे कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तय वजन सीमा तक पर्सनल लगेज की ऑनलाइन बुकिंग लागू करें। इस सुविधा से यात्री उस सामान की बुकिंग कर सकेंगे जिसे वे रिजर्व्ड डिब्बों में अपने साथ ले जाते हैं।

इसमें कहा गया है कि ऊपर बताए गए इस ऑफिस के 7 मार्च 2025 के लैटर (Ref। 1) के

तहत, सैद्धांतिक रूप से यह तय किया गया था कि केवल कंफर्म टिकट पर रिजर्व्ड डिब्बे में यात्री के साथ ले जाए जाने वाले पर्सनल लगेज की अधिकतम तय वजन सीमा तक ऑनलाइन बुकिंग लागू की जाए। इसे ध्यान में रखते हुए, 31 जुलाई 2026 से लगेज की ऑनलाइन बुकिंग लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इंडियन रेलवे लगेज बुकिंग

सभी जोनल रेलवे को भेजे गए 7 मार्च, 2025 के एक पत्र में, रेलवे बोर्ड (RB) ने कहा कि AC 3-टियर (3AC), AC 3 इकोनॉमी (3E) और AC चेयर कार (CC) के लिए फ्री लगेज अलाउंस और अधिकतम स्वीकार्य अलाउंस एक ही हैं। इन क्लास में अतिरिक्त लगेज की बुकिंग की अनुमति नहीं होगी, सिवाय उन मामलों के जहां फ्री लगेज अलाउंस पर ही शुल्क लगता हो। निर्देश में कहा गया है कि लगेज बुकिंग से जुड़ी अन्य सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया के दौरान प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची (जिन्हें लगेज के तौर पर बुक नहीं किया जा सकता), क्लास-वार फ्री अलाउंस, डिब्बे के अंदर बुक किए जा सकने वाले अधिकतम वजन की सीमा, और डिब्बे के अंदर तय सीमा से ज्यादा लगेज ले जाने पर जुर्माने के प्रावधान आदि की जानकारी दिखाई जाएगी।

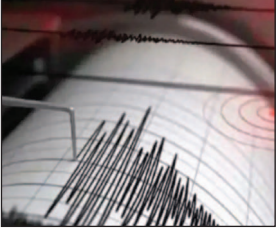
भारतीय रेलवे में सामान के वन की सीमा

रेलवे बोर्ड के फ्रेट मार्केटिंग सर्कुलर नंबर 38 (2006) के अनुसार, प्रति यात्री फ्री सामान की सीमा इस प्रकार है: फर्स्ट AC में 70 किलोग्राम, फर्स्ट क्लास और सेकंड AC में 50 किलोग्राम, थर्ड AC (3AC), AC चेयर कार (CC) और स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम, और सेकंड क्लास में 35 किलोग्राम। हालांकि, यात्री मुफ्त सीमा से ज्यादा सामान रिजर्व्ड डिब्बे में ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें तय नियमों के अनुसार अधिकतम सीमा तक लागू सामान दर का 1।5 गुना शुल्क देना होगा।

भारतीय रेलवे के सामान से जुड़े नियम

नियमों के अनुसार, 100 सेमी × 60 सेमी × 25 सेमी (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) के बाहरी माप वाले टंक, सूटकेस और बक्सों को यात्री डिब्बों में निजी सामान के तौर पर ले जाने की अनुमति है। सर्कुलर में कहा गया है कि अगर टंक, सूटकेस और बक्सों का बाहरी माप इनमें से किसी भी डाइमेंशन (लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई) से ज्यादा है, तो ऐसे सामान को ब्रेक-वैन में बुक करके ले जाना होगा, न कि यात्री डिब्बों में। व्यावसायिक माल को यात्री डिब्बे में निजी सामान के तौर पर बुक करने या ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

भूकंप से दहला मिस्र, म्यांमार में भी डोली धरती



मिस्र, एजेंसी। मिस्र के पास सुबह तड़के 5।4 तीव्रता का भूकंप आया। आस-पास के इलाके हिल गए और जोर से कंपन हुआ। ये भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। म्यांमार में भी भूकंप के झटके महसूस हुए, इसकी तीव्रता 3।3 रही। मिस्र के अधिकारियों ने बाद में बताया कि भूकंप का केंद्र स्वेज शहर से 38 किलोमीटर दूर था। पहले जर्मन रिसर्च सेंटर ने इसे स्वेज के पास बताया था, जबकि EMSC ने स्वेज से करीब 29 किलोमीटर उत्तर-

पश्चिम में बताया। मिस्र के रेड क्रिसेंट ने उन इलाकों में आपातकालीन प्लान सक्रिय कर दिया जहां झटके महसूस हुए।अभी तक किसी के घायल होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है।

रेड क्रिसेंट ने निवासियों से अपील की कि वे नुकसान के संकेत वाली इमारतों से दूर रहें और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, क्योंकि अधिकारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं।

मिस्र के स्वास्थ्य मंत्री खालिद अब्देल गफ्फार ने पूरे देश में इमरजेंसी रिसपॉन्स प्लान लागू करने का आदेश दिया और एम्बुलेंस सेवाओं को “पूरी तरह तैयार” रहने का निर्देश दिया। मिस्र और व्यापक पूर्वी भूयध्यसागरीय क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र में स्थित हैं। इस तीव्रता के भूकंप समय-समय पर इस

इलाके में आते रहते हैं, हालांकि इनसे आमतौर पर बहुत कम या कोई नुकसान नहीं होता है। इसकी और जानकारी के लिए अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

म्यांमार में भी आया भूकंप

म्यांमार में भी 3 अगस्त को सुबह-सवेरे भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। इसकी तीव्रता 3।3 रही। ये भूकंप भूकंप 105 किलोमीटर की गहराई पर आया। यहां पर किसी तरह के कोई नुकसान की सूचना नहीं है। पूर्वोत्तर अफ्रीका के इस देश में जबरदस्त भूकंप कम ही आते हैं। आधुनिक इतिहास में देश का सबसे घातक भूकंप अक्टूबर 1992 में आया था, जब 5।8 तीव्रता के भूकंप ने राजधानी को हिला दिया था। इसमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और हजारों लोग बेघर हो गए।

ट्रंप ने रोका युद्ध! आज से शुरू होगी US-ईरान की बातचीत, होर्मुज और परमाणु डील पर उम्मीद

तेल अवीव, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान के साथ शुरू होने वाली बातचीत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने एटर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चर्चा के रास्ते पहले से खुले हुए हैं और बातचीत आज दोपहर से यानी 3 अगस्त से शुरू होगी। उन्होंने कहा हम देखेंगे कि ये कैसी रहती है? मैं सच कहूँ तो, इससे बहुत सारी जानें बचेगी और बहुत सारी बेकार की ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा। हम जब चाहें तब आगे बढ़ने को तैयार हैं। वे युद्ध या हिंसा नहीं चाहते, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। वे समझौता (डील) करना पसंद करेंगे। उन्होंने बताया कि ईरान और कुछ अन्य देशों ने खुद अमेरिका से बातचीत शुरू करने को कहा है,



इसलिए वे बातचीत के लिए तैयार हैं।

ट्रंप ने बातचीत में बताया कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और ईरान के साथ हुई बातचीत के कारण ही उन्होंने शुक्रवार को होने वाले “बड़े हमले” को रोक दिया। ट्रंप ने ये भी संकेत दिया कि होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही

उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के परमाणु-निरस्त्रीकरण (denuclearisation) को लेकर भी एक समझौता किया जाएगा।

होर्मुज स्ट्रेट पर बातचीत बनाने पर जोर

कूटनीति की तरफ ये अचानक रुख ऐसे समय में आया है जब

मध्यस्थ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को इजरायली मीडिया ने बताया कि क्षेत्रीय मध्यस्थ पिछले महीने हुए समझौते को फिर से लागू करना चाहते हैं, ताकि महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता 60 दिन तक खुला रहे। साथ ही इस रास्ते पर आवाजाही के लिए किसी तरह की कोई फीस न लगे। इसी तरह, ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि समुद्री रास्ते के चलाने को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत भी आखिरी स्टेज तक पहुंच चुकी है।

पहले टूट चुका है समझौता

शुरुआती समझौता पहले ही टूट गया था। ट्रंप का कहना था कि रास्ता हमेशा खुला रहेगा। तेहरान का मानना

था कि उस रास्ते पर उनका पूरा अधिकार बना रहेगा। इस हफ्ते पर्दे के पीछे की बातचीत ने युद्ध रोकने में बड़ी मदद की। कतर के अधिकारियों ने ईरान, अमेरिका और ओमान से बात की। उन्होंने शनिवार को ट्रंप को बताया कि ईरान ने स्ट्रेट डाला प्रस्ताव मान लिया है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी ट्रंप से फोन पर बात की और सैन्य कार्रवाई न करने को कहा। इन बातों के बाद ट्रंप ने दुथ सोशल पर कहा कि वो हमले रोक रहे हैं। उन्होंने शिपिंग मार्ग और परमाणु मुद्दे में प्राति का हवाला दिया। यहां रविवार रात कोई हमला नहीं हुआ। वहीं इरानी सैन्य नेताओं ने ट्रंप के दावे को झूठ बताया। तेहरान के एक सूत्र ने कहा कि स्ट्रेट पर अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है।

ढाका से चटगांव तक मिले 103 विस्फोटक. . . बांग्लादेश की गली-गली में बम क्यों मिल रहे हैं?

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। देशभर में संभावित बम हमले की आशंका के बाद पुलिस ने सभी इकाइयों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। पुलिस का कहना है कि कुछ खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह आशंका जताई गई है कि पुलिसकर्मियों और पुलिस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। इसी वजह से पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

संवेदनशील इलाकों, सरकारी संस्थानों, प्रमुख सड़कों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अग्रिय घटना को पहले ही रोका जा सके। पुलिस अधिकारियों को संहिध गतिविधियों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अलर्ट के बाद आम लोगों से भी अपील की गई है कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, सामान या गतिविधि की जानकारी



तुरंत पुलिस को दें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना केवल प्रशासन ही नहीं, बल्कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है।

बम और बम जैसी वस्तुएं बरामद हुई हैं

बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से अलग-अलग जगहों पर बम और बम जैसी वस्तुएं मिलने की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को चिंता बढ़ा दी है। ढाका के अशुलिया में रिमोट कंट्रोल से लैस आईईडी जैसा बम मिला, जबकि 24 जुलाई को मोतीशील मेट्रो स्टेशन के नीचे टाइमर लगा पाइप बम बरामद हुआ था। सीटीटीसी इन मामलों की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि इनके पीछे कौन है। वहीं फार्मीगेट और मीरपुर-10 मेट्रो स्टेशनों पर मिली संदिग्ध वस्तुएं जांच में बम नहीं निकलीं।

राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा अलर्ट

बांग्लादेश पुलिस का यह हाई अलर्ट ऐसे समय जारी किया गया है,

जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार हटने की दूसरी वर्षगांठ नजदीक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों में देश का सबसे प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा सकता है। इसी इनपुट के आधार पर देशभर की पुलिस इकाइयों को अतिरिक्त सतर्क रहने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।

पूरे देश में बढ़ाई गई निगरानी

पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने, लेकिन अफवाहों से बचने और घबराने की जरूरत नहीं होने की अपील की है। यह अलर्ट ऐसे समय जारी किया गया है जब देश में राजनीतिक माहौल भी संवेदनशील बना हुआ है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों की पुलिस, महानगर पुलिस और अन्य सुरक्षा इकाइयों को

सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रमुख सरकारी भवनों, पुलिस कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नियमित गश्त के साथ-साथ संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच भी तेज कर दी गई है।

पुलिसकर्मियों को दिए गए विशेष निर्देश

रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस अधिकारियों और जवानों को ड्यूटी के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। पुलिस वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने, सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करने और किसी भी संदिग्ध सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा करें।

आम लोगों से भी सहयोग की अपील

पुलिस ने नागरिकों से कहा है कि यदि उन्हें कोई लावारिस वस्तु, संदिग्ध व्यक्ति या असामान्य गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दें। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली अपुष्ट खबरों और अफवाहों से बचने की भी अपील की गई है, ताकि अनावश्यक दहशत न फैले। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि खुफिया सूचनाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है और हालात के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा।

अब तक कितने बम मिले हैं?

जनवरी 2026 से अब तक बांग्लादेश में कम से कम 103 असली बम और आईईडी बरामद किए जा चुके हैं। इनमें सबसे बड़ी बरामदगी 2 फरवरी को शरियतपुर जिले में हुई, जहां संयुक्त बलों ने 95 देसी (कूड) बम बरामद किए थे। इसके बाद 8 मार्च को ढाका स्थित सुप्रीम कोर्ट के जजों के एंट्री गेट के

पास 6 कूड बम मिले, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। वहीं 24 जुलाई को ढाका के मोतीशील मेट्रो स्टेशन के नीचे एक पाइप बम (IED) मिला, जबकि जुलाई के आखिर में अशुलिया इलाके से एक प्रेशर कुकर IED बरामद किया गया। इसके अलावा फार्मीगेट और मीरपुर-10 मेट्रो स्टेशनों पर दो संदिग्ध बम जैसी वस्तुएं भी मिली थीं, लेकिन जांच में वे बम नहीं निकलीं। इस तरह जनवरी 2026 से अब तक बांग्लादेश में 103 असली बम और आईईडी मिलने के मामले सामने आए हैं।

किन जगहों पर बढ़ाई गई निगरानी?

हाई अलर्ट के बाद एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, सरकारी कार्यालयों, अदालतों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया

गया है, वाहनों की जांच और सीसीटीवी निगरानी तेज कर दी गई है। सीटीटीसी का कहना है कि फिलहाल 5 अगस्त को लेकर किसी साजिश की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे देश में कड़ी सतर्कता बरती जा रही है।

पुलिस वाहनों पर निगरानी

खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद खास तौर पर पुलिस और अन्य कानून-व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों के वाहनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की जीप, ट्रक और बसों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की ऑपरेशंस कंट्रोल ब्रांच (OCB) ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया है कि सरकारी वाहनों की सुरक्षा चलते समय ही नहीं, बल्कि पार्किंग के दौरान भी सुनिश्चित की जाए। किसी भी वाहन को बिना निगरानी के न छोड़ने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है।



बरी होने के बाद बोले बृजभूषण-जंतर मंतर से मुझे फांसी और जिंदा जलाने की मांग हो रही थी

नई दिल्ली, एजेंसी। महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी के पूर्व सांसद वृज भूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार (3 जुलाई) को इस मामले में उन्हें बरी कर दिया है। उनके साथ ही विनोद तोमर को भी बरी कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद वृज भूषण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है।

वृज भूषण सिंह ने कहा कि जिस दिन उनके ऊपर आरोप लगा था उन्होंने तभी कह दिया था कि अगर आरोप साबित हो जाएगा तो वो खुद फांसी पर लटक जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी दिया ऐसे में ये उनके लिए और उनके समर्थकों के लिए बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा'।

वृज भूषण शरण सिंह ने कहा



'18 जनवरी 2023 को मैंने कहा था कि ये एक षड्यंत्र है। अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद तोमर का बरी किया

है'। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर से उन्हें फांसी और जिंदा जलाने की मांग हो रही थी।

‘मुझे विश्वास था न्याय होगा’

उन्होंने कहा 'मैं 15-16 साल

की उम्र से संघर्ष देख रहा हूं। मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था। मुझे अपने आप पर विश्वास था। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा। और आज मेरे साथ न्याय हुआ। मैंने अपने आप

को कभी अपराधी महसूस नहीं किया'।

‘जो कहा था वो सच साबित हुआ’

वृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने जो कहा था वो सच साबित हुआ और कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मेरे और मेरे समर्थकों के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि आज खुशी का दिन है, ऐसे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हो गया, सो हो गया।

बृजभूषण शरण के बेटे ने क्या कहा

वहीं कोर्ट के फैसले पर वृजभूषण शरण के बेटे और बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने खुशी जाहिर की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा 'मैं कोर्ट का शुक्रिया

अदा करना चाहता हूं। यह सच्चाई, युवा पहलवानों और कैसरगंज की जीत है। आज हम देश के सामने मजबूती से खड़े हैं। जो पार्टियां उस समय मेरे पिता के खिलाफ बोल रही थीं, क्या वे आगे आकर कहेंगी कि उनके साथ जो हुआ, वह गलत था?'।

बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार

वृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। वो उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से बीजेपी के 6 बार सांसद रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के चलते 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने इन आरोपों के बीच भी शानदार जीत दर्ज की थी।

सीएम की जासूसी, हनीट्रैप की साजिश : अब एसटीएफ के हथ्थे चढ़ा हमीम का दूसरा साथी, क्या बंगाल में पैर फैला रहा जैश ?

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने आतंकी और आपराधिक नेटवर्क के एक ऐसे बड़े जाल को ध्वस्त किया है, जो राज्य के बड़े नेताओं को ब्लैकमेल करने और अपहरण करने की तैयारी में था। पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के संदिग्ध सहयोगी हमीम मंडल के दूसरे सबसे करीबी मददगार आदित्य सिंह उर्फ राज को हावड़ा के बेलिलियस रोड स्थित उसके ठिकाने से धर दबोचा है। क्राइम की इस पूरी पटकथा में आदित्य सिंह उर्फ राज की भूमिका एक 'लोकल खबरी' और 'जासूस' की थी। हावड़ा के बेलिलियस रोड रहने वाला आदित्य लगातार भाजपा विधायक और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में राज्य मंत्री उमेश राय की रेकी कर रहा था। वह मंत्री और उनके परिजनों की पल-पल की मूवमेंट की जानकारी मुख्य आरोपी हमीम मंडल तक पहुंचाता था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद

मंत्री उमेश राय को जो धमकी भरा कॉल आया था, उसके पीछे भी इसी आदित्य सिंह का हाथ होने की बात सामने आई है। इस गैंग का मकसद बेहद खतरनाक था। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर यह सिंडिकेट बड़े नेताओं और प्रभावशाली लोगों के बच्चों व रिश्तेदारों को सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसाता था। मॉडल और रील बनाने की शौकीन अर्पिता सरकार जैसी सहयोगियों के जरिए टारगेट को प्यार के जाल में फंसाकर (हनीट्रैप) ब्लैकमेल किया जाता था। अगर ब्लैकमेलिंग से बात नहीं बनती, तो अपहरण (किडनैपिंग) करके मोटी रकम वसूलने की पूरी योजना तैयार थी। इस पूरे केस की कड़ियां एक-एक करके खुलतीं। एसटीएफ ने सबसे पहले मुख्य आरोपी हमीम मंडल को बर्धमान शहर से दबोचा था। उसी रात उसकी महिला सहयोगी अर्पिता सरकार को झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया गया। दोनों से जब एसटीएफ की कस्टडी में कड़ाई से पूछताछ हुई।

'कई आर्टिस्ट के लिए नए रास्ते खोले हैं', अपने नए गाने को लेकर उत्साहित नोरा फतेही, कही ये बात

नोरा फतेही ने अपने नए गाने 'स्ले टू द रिदम' को लेकर उत्साह जाहिर किया है। उन्होंने बताया है कि यह गाना क्यूं बहुत खास है। उन्होंने इसे गर्मियों का गाना कहा है।

अभिनेत्री और गायिका नोरा फतेही ने हाल ही में अपना नया गाना 'स्ले टू द रिदम' रिलीज किया है। इस गाने को संजॉय ने लिखा है और इसमें यासीन इदरीसी और नोरा फतेही की आवाज है।

'चैपियंस' और 'लॉकड इन' की कामयाबी के बाद नए गाने 'स्ले टू द रिदम' ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया है। यह गाना अपनी शानदार बीट्स, जोश भरे विजुअल्स, जबरदस्त रिदम के साथ डांस और म्यूजिक को लेकर चर्चा में है। जब से इसकी पहली झलक सामने आई है, फैंस इसका आनंद ले रहे हैं।

गर्मियों का है गाना

नोरा फतेही ने इस नए गाने को लेकर अपना उत्साह जाहिर



करते हुए इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, 'यह गर्मियों का एक जबरदस्त गाना है। यह दुनिया भर के म्यूजिक और डांसर्स को एक ट्रिव्यूट है। यह गाना इस बात का सबूत है कि कैसे

इसने दुनियाभर के लोगों को जोड़ा है। इसने मुझ जैसे आर्टिस्ट के लिए कई रास्ते खोले हैं। यह म्यूजिक और डांस का जश्न है।'

कई रास्ते खुले

उन्होंने कहा, 'ये दोनों चीजें ही हैं जिन्होंने मेरे लिए कई रास्ते खोले और मुझे आप सभी से जोड़ा! डांस और म्यूजिक ने

मुझे दुनिया भर की सैर कराई और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया! मुझे उम्मीद है कि यह गाना आपको समाज की सोच से आजाद होने और हमेशा अपने दिल की बात सुनने के लिए प्रेरित करेगा।'

गाने के आखिर में दिया गया क्रेडिट

म्यूजिक वीडियो में शामिल सभी डांसर्स और परफॉर्मर्स को गाने के आखिर में क्रेडिट दिया गया है और उनके योगदान को दिखाने के लिए उन्हें खास स्क्रीन टाइम भी दिया गया है।

नोरा नए आर्टिस्ट्स को देती हैं प्लेटफॉर्म

नोरा अपने चल रहे 'डांस विद नोरा' प्रोजेक्ट के जरिए दुनिया भर के डांसर्स, परफॉर्मर्स और नए आर्टिस्ट्स को एक प्लेटफॉर्म देती रहती हैं।

यह प्रोग्राम युवा टैलेंट को अपनी काबिलियत दिखाने, पहचान बनाने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अपना जोश बनाए रखने में मदद करता है।

विक्रम का चियान 63 में लुक देख उड़ गए होश, फैस बोले– अब फिल्म का इंतजार नहीं होता

चियान विक्रम ने अपनी आने वाली फ़िल्म, जिसका अभी अस्थायी नाम चियान 63 रखा गया है, के बारे में एक नए अपडेट से एक बार फिर फ़ैनस का ध्यान खींचा है। उनके बेटे ध्रुव विक्रम द्वारा शेयर किए गए विहाईड-द-सीन्स वीडियो से सोशल मीडिया पर काफ़ी उत्साह पैदा हुआ था। अब डायरेक्टर आनंद शंकर द्वारा फ़िल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल के पूरा होने की घोषणा के साथ ही एक्टर फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस अपडेट ने इस एक्शन एंटरटेनर फ़िल्म के लिए उत्साह और बढ़ा दिया है, क्योंकि फ़ैंस विक्रम को लगभग एक दशक बाद इस फ़िल्ममेकर के साथ काम करते देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

डायरेक्टर आनंद शंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि चियान 63 का पहला शेड्यूल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। उन्होंने इस घोषणा के साथ विक्रम की एक स्टार्गलिश नई तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें एक्टर ने डार्क सनग्लासेस पहने हुए हैं और हाथ में आग की लपट पकड़े हुए हैं, जिसकी झलक उनके चश्मे के लेंस पर दिख रही है। यह शानदार तस्वीर वायरल हो गई और फैंस ने कमेंट सेक्शन में अपना उत्साह जाहिर किया। कई लोगों ने इसे जबरदस्त अपडेट कहा और कहा कि वे बड़े पर्दे पर विक्रम का नया अवतार देखने के लिए बेताब हैं। इस घोषणा से यह भी कन्फर्म हुआ कि टीम जल्द ही फ़ॉलोअप का आला चरण शुरू करेगी, जिससे प्रोजेक्ट तय समय पर चलता रहेगा।

चियान 63 विक्रम और आनंद शंकर की दूसरी फ़िल्म है; इससे पहले उन्होंने 2016 की एक्शन थ्रिलर इरु मुगन में साथ काम किया था।



उनकी पिछली फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर सफल रही थी और सालों में उनकी एक वफ़ादार फ़ैन फ़्रॉलोइंग बन गई है। इस बार उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, खासकर विक्रम की हालिया रिलीज़ वीरा धीरा सूरन की मिली तारीफ़ के बाद। एक्टर ने अपने नए रोल के लिए काफ़ी फ़ज़्ज़िकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी किया है और उनका रफ़ लुक पहले से ही फ़िल्म की सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक बन गया है।

ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में मोनालिसा का बोल्ड अंदाज, फ्लोरल टियारा ने लूटी महफिल

भोजपुरी सिनेमा से लेकर टीवी जगत तक अपनी बोल्डनेस और बेहतरीन अदाकारी से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया फोटोशूट शेयर किया है, जिसमें उनका बेहद ग्लैमरस और बोल्ड अवतार देखने को मिल रहा है। मोनालिसा ने इस फोटोशूट के लिए एक बेहद हॉट लिटिल ब्लैक ड्रेस को चुना है। उनकी यह ड्रेस मिनी बॉडीकॉन स्टाइल में है, जिसमें नेकलाइन और वेस्ट एरिया पर ट्रांसपेरेंट मेश फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है।

यह डीप-नेक मेश आउटफिट मोनालिसा के कर्वी और परफेक्ट फिगर को बेहद खूबसूरती से उभार रहा है, जो उनके लुक में बोल्डनेस का तड़का लगा रहा है। तस्वीरों में मोनालिसा एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। कभी वे अपने दोनों हाथों को बालों पर रखकर सिजलिंग पोज दे रही हैं, तो कभी दीवार और चेयर के सहारे टिककर उनके कातिलाना एक्सप्रेशंस फैंस को दीवाना बना रहे हैं। मोनालिसा ने अपने इस ग्लैम लुक को कम्प्लीट करने के लिए बालों को मिडिल पार्टिंग

के साथ सॉफ्ट कर्ल्स देकर खुला छोड़ा है। कुछ तस्वीरों में वे अपने सिर पर लाल गुलाब के फूलों से बना एक खूबसूरत फ्लोरल टियारा पहने नजर आ रही हैं। डार्क मैरून लिपस्टिक, वेल-शेड आईब्रो

और मिनिमल मेकअप मोनालिसा के फेशियल फीचर्स को परफेक्टली हाइलाइट कर रहा है। मोनालिसा का यह लेटेस्ट ब्लैक मेश ड्रेस लुक इंटरनेट पर जमकर ट्रेंड कर रहा है।

